बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 187 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 25 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाई कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली पद की शपथ, कुल जजों की संख्या हुई 43

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार को गुरुवार को औपचारिक रूप से शपथ दिलाई गई। इससे न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 43 हो गई, जबकि स्वीकृत कुल न्यायाधीशों की संख्या 60 है। इससे पहले हाईकोर्ट में सोमवार को छह नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति विनोद कुमार, न्यायमूर्ति शैल जैन और न्यायमूर्ति मधु जैन को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया।

हंगामे के भेंट चढ़ा मानसून सत्र का चौथा दिन, लोकसभा-राज्यसभा शुक्रवार तक स्थगित

नई दिल्ली। मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले, विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित अन्य मुद्दों को लेकर संसद के मकर द्वार पर फिर से विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के पहले तीन दिन इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों के कारण लगभग बिना किसी कार्यवाही के ही बीत गए, जिसके कारण बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। आपको बता दें कि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर एसआईआर अभ्यास, ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर बातचीत करने के डोनाल्ड ट्रम्प के बार-बार दावों पर बहस के लिए दबाव बनाना जारी रखा है, साथ ही सत्र के पहले दिन के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर जवाब मांग रहा है।

लोकसभा की कार्यवाही

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (एमसीएफ) में संविदा कर्मचारियों को वेतन वितरण में किसी भी तरह की

गड़बड़ी को रोकने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों को आड़े-हाथों लिया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के संस्कार सदन में नारेबाजी करने, तख्तियां लाने और मेजें थपथपाने के लिए नहीं रहे हैं, लेकिन इस दल के मौजूदा सांसदों का आचरण पूरा देश देख रहा है।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बैठक लगातार चौथे दिन बाधित रही और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर पंद्रह मिनट पर कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को उन छह सदस्यों को विदाई दी गई जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिनमें से एक उच सदन के लिए पहले ही पुनर्निर्वाचित हो चुके हैं। सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि छह सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें एक, अन्नाद्रमुक के पी विल्सन दूसरे कार्यकाल के लिए सदन में वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि द्रमुक के एम मोहम्मद अब्दुल्ला और एन षणमुगम, अन्नाद्रमुक के एम चंद्रशेखरन और पी विल्सन, पीएमके के डॉ अंबुमणि रामदॉस तथा एमडीएमके के एम वाइको का उच सदन में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को वरिष्ठ वकील एवं न्यायविद् उज्वल निकम ने मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। निकम ने मराठी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया।

तख्तियां-नारेबाजी कांग्रेस के संस्कार नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले- नई पीढ़ी क्या सीखेगी?

नई दिल्ली। विपक्ष बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर विरोध कर रहा है। संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हो रहा है। गुरुवार को भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं हैं। उन्होंने सांसदों से स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। दरअसल गुरुवार को संसद सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल के दौरान जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तब भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी। इससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस सांसदों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है। सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन सांसदों का व्यवहार संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप देश की इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, जिनका इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा का इतिहास रहा है, लेकिन आप सदन में नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं और मेजें ठोकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम जिस तरह का व्यवहार करेंगे, उसका देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्या संदेश जाएगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का नाम लेकर कहा कि ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं हैं। आपको लोगों ने चुनकर भेजा है। अपनी आकांक्षाएं साझा करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन तख्तियां लेकर आने और नारेबाजी से सदन नहीं चलेगा। ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों को सलाह देते हुए कहा कि नई पीढ़ी आपको देख रही है, वो इससे क्या सीख लेगी। नियमों के तहत सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

मोहन भागवत से मुलाकात पर इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी बोले, गलतफहमियां दोनों तरफ...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी की मौजूदगी में धार्मिक नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक के बाद इलियासी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है .अखिल भारतीय इमाम संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साझा प्रयास से संवाद किया गया. उन्होंने कहा, पिछली बार भी हमने मोहन भागवत को इमाम हाउस आने के लिए निमंत्रण दिया था और वो हमारे साथ मदरसा भी गए थे. उसी कड़ी में आज ये संवाद हुआ है. देशभर के बड़े इमाम, मुफ्ती, मदरसों के चीफ समेत 60 लोगों ने इस 3.5 घंटे चली बैठक में हिस्सा लिया है. लंबा संवाद होने के बाद तय हुआ हम इस तरह के संवाद और करेंगे. उमर अहमद इलियासी ने कहा, संवाद हर समस्या का हल है! संवाद होते रहना चाहिए! संवाद से गलतफहमी दूर होती है! संवाद से नफरत खत्म होती है! संवाद से मोहब्बतें बढ़ती हैं! हमारी जातियां, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, राष्ट्र सर्वोपरि है. उन्होंने कहा, गलतफहमियां दोनों तरह हैं, उस तरफ और इस तरफ की गलतफहमी है, जिसे दूर किया जाएगा, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर इलियासी ने कहा कि संवाद हर समस्या का समाधान है, जहां समस्या है, वहां संवाद है. संवाद की जरूरत है. सीएम ने कहा है कि मौजूदा वृद्धि दर जारी रही तो 2041 तक असम में मुस्लिम जनसंख्या लगभग हिंदुओं के समान हो जाएगी. डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी के नेतृत्व में लगभग 60 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार मौजूद रहे. मुस्लिम पक्ष से ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मुफ्ती सैयद, शाही इमाम लखनऊ सैय्यद शाह फजलुल मलन रहमानी, जुबैर गोफ्तानी शामिल हुए.

सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एलान, दिल्ली वालों को मिलेगी 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर की सौगात

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नागरिकों को 93 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का दावा करते हुए मार्च 2026 तक 1,100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएमएस) शुरू करने की घोषणा की। 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएमएस) का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली को लगातार एक वरदान मिल रहा है और वह है आयुष्मान भाव। एक के बाद एक स्वास्थ्य सुविधाओं का जुड़ना, दिल्ली को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली को स्वस्थ बनाना, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और पूरी व्यवस्था का डिजिटलीकरण करना हमारा लक्ष्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे 93 लाख आभा कार्ड नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। इसे आयुष्मान कार्ड भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, आयुष्मान योजना के

तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है और 2,000 से ज्यादा लोगों ने इसके तहत सेवाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत लगभग 3 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली एक स्वस्थ शहर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य ढांचे और सभी की देखभाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 34 एएएम का शुभारंभ सरकार द्वारा घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का नवीनतम प्रयास है।

150 डायलिसिस केंद्र भी खोले गए- सीएम रेखा गुप्ता

उन्होंने कहा, हमने 150 डायलिसिस केंद्र भी खोले हैं और जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का विस्तार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) सुविधाएं भी शुरू करने जा रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्तियों को भरने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम प्रधानमंत्री द्वारा दिल्लीवासियों से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें दवाएं और स्वास्थ्य ढांचा शामिल हैं।

पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर भी निशाना साधा

उन्होंने शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति के लिए पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार हालत सुधारने के लिए काम कर रही है। मंत्री सिंह ने पहले कहा था कि अगस्त के अंत तक 75 अतिरिक्त आम आदमी पार्टी केंद्र स्थापित कर जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसी) के कुल 429 स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 98 को अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है।

अवैध धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के दो बेटे और बहू गिरफ्तार, पत्नी फरार

नई दिल्ली। यूपी के छांगुर बाबा का मामला अभी सुर्खियां बटोर ही रहा था कि दिल्ली में भी अवैध धर्मांतरण गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का और उसका पूरा परिवार शामिल निकला. पुलिस ने रहमान के दो बेटों अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम के साथ बहू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी पत्नी फरार हो गई है. ये गिरोह युवतियों को फंसाकर जबरन धर्मांतरण कराता था और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे. पुलिस इस मामले को अंतरराष्ट्रीय और सुनियोजित नेटवर्क मानकर जांच में जुट गई है. दरअसल पुलिस ने एक दलित युवती के जबरन निकाह के मामले में जुनैद नामक युवक को गिरफ्तार किया, जो इसी गिरोह से जुड़ा था. पूछताछ के बाद अब्दुल रहमान के बेटों और बहू की संलिप्तता सामने आई. जब पुलिस ने छापेमारी की तो आरोपियों के पास से संदिग्ध धार्मिक साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और फर्जी दस्तावेज मिले. वहीं अब्दुल रहमान की पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह लड़कियों को धर्मांतरण के लिए लाने की बात कह रही है. पुलिस जब रहमान के घर दबिश देने पहुंची, तो उसकी पत्नी मौके से फरार हो गई. पुलिस ने उसकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं. वहीं, अब्दुल रहमान के मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि इस गिरोह के फंडिंग नेटवर्क और अन्य कनेक्शन का पता लगाया जा सके. प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हो सकता है और इसे योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था. इस गिरोह का मकसद खासतौर पर दलित और कमजोर वर्ग की युवतियों को निशाना बनाना था. उन्हें प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता था और फिर निकाह कर फर्जी पहचान पत्र तैयार किए जाते थे. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क से और भी लोग जुड़े हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

नॉर्थ ब्लॉक से गृह मंत्रालय के कार्यालय की शिफ्टिंग शुरू, नए सीसीएस-3 भवन में हो रहा स्थानांतरित

नई दिल्ली।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राजधानी के हृदय स्थल को नया रूप देने की नरेंद्र मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा योजना के तहत, रायसीना हिल्स स्थित ब्रिटिशकालीन नॉर्थ ब्लॉक से इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर स्थित एक नए भवन में कार्यालय स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और कुछ संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी और उनके कर्मचारी पहले ही नवनिर्मित सीसीएस-3 भवन में स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि शेष अधिकारी और अन्य कर्मचारी अगले कुछ दिनों में स्थानांतरित हो जाएँगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यालय अभी स्थानांतरित नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रक्रिया चल रही है। नए भवन में गृह मंत्रालय को लगभग 350 कमरे आवंटित किए गए हैं। नॉर्थ ब्लॉक स्थित लाल बलुआ पत्थर से बनी यह इमारत लगभग 90 वर्षों से गृह मंत्रालय का मुख्यालय रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख कार्यालयों वाली नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी एक जैसी इमारतें नए भवन बनने के बाद पूरी तरह खाली हो जाएँगी। सरकार की योजना के अनुसार, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के कार्यालय खाली होने के बाद, वहाँ एक विशाल संग्रहालय - युगे युगीन भारत - बनाया जाएगा। 1.55 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल और 950 कमरों वाला यह संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक होगा। ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सहित सचिवालय भवनों के साथ-साथ संसद भवन और कई बंगलों का डिज़ाइन तैयार किया था। बेकर ने नई दिल्ली की समग्र योजना पर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर काम किया था।

दिल्ली में 10 लाख की साइबर ठगी: पुलिस ने गैंग का किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने साइबर गैंग से जुड़े दो ठग को अरेस्ट किया है. यह ठग मोबाइल को हैक करके भोले भाले लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा देते थे. दिल्ली पुलिस ने शंकर दान और प्रदीप कुमार दान नाम से साइबर ठग को धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन दोनों ठगों ने एक व्यक्ति को बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और चेक बाउंस की बात कहकर APK फाइल व्हाट्सऐप पर भेजी, फाइल इंस्टॉल करते ही आरोपी ने बैंक अकाउंट पर नियंत्रण पा लिया और 10 लाख 64 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया. पीड़ित के दो फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़े गए एक 5 लाख 62 हजार और दूसरा 4 लाख 54 हजार का. साथ ही 48 हजार 600 गूगल एड्स के जरिए खर्च किया गया. दिल्ली पुलिस ने ठगी के इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन किया . साइबर सेल की टीम ने कॉलिंग नंबर और मनी ट्रेल के जरिए जांच शुरू की. तब पता चला कि ठगी की रकम को बिल डेस्क प्लेटफॉर्म पर भेजा गया जहां से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स और गूगल एड्स के पेमेंट में इस्तेमाल किया गया. टेक्निकल सर्विलांस में मोबाइल लोकेशन धनबाद, झारखंड में मिली. टीम ने धनबाद, बोकारो, रांची और बीरभूम में लगातार छापे मारे और बाद में दोनों आरोपियों को धर दबोचा. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी शंकर दान 3वीं तक पढ़ा हुआ. आरोपी शंकर पहले से दो साइबर क्राइम और हत्या के मामले में नामजद है. आरोपी शंकर अमेजॉन पर एप के जरिए मोबाइल नंबर हासकर पीड़ितों के बैंक का नाम पता करता था.फिर उन्हें केवाईसी अपडेट कार्ड ब्लॉक या चेक बाउंस के बहाने कॉल करता।

दिल्ली में सास-ससुर और बहू की ठग तिकड़ी गिरफ्तार, फिल्मी स्क्रिप्ट लिख महिलाओं बनाते थे शिकार

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर घूमती थी एक ऐसी तिकड़ी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये ठगी की ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे है जो फिल्मों को भी पीछे छोड़ दे. इस गिरोह में सास-ससुर और बहू की ऐसी जोड़ी थी, जो महिलाओं को नकली नोट दिखाकर उनकी जूलरी उड़ा लेती थी. लेकिन आखिरकार, पुलिस की पैनी नजर ने इनका खेल खत्म कर दिया. बाहरी दिल्ली के रघुवीर नगर में रहने वाला लक्ष्मण इस फैमिली ठग गैंग का मास्टरमाइंड निकला, जो अपनी पत्नी और बहू के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था. रणहौला थाना और स्पेशल स्टाफ की जॉइंट टीम ने तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. ये तिकड़ी खास तौर पर लोकल बाजार और मंदिरों के आसपास मंडराती थी. अकेली चल रही महिलाओं को ये अपनी बातों में उलझाते, और फिर नकली नोटों का बंडल दिखाकर उन्हें झांसे में लेते. बातों ही बातों में महिलाएं अपनी सोने की जूलरी उतार देतीं और बदले में पकड़ाया जाता नकली नोटों से भरा पैकेट. सास-बहू महिला होने का फायदा उठाकर पहले भरोसा जीततीं, फिर ससुर यानी लक्ष्मण मौके पर 'मीरियम' बात करने वाला बनकर आता और सम्मोहित कर महिलाओं के गहने उतरवाने के बाद सभी फरार हो जाते थे. इनका टीम वर्क इतना परफेक्ट था कि, ये तीनों किसी को शक नहीं होने देते थे कि उनके पीछे ठगी की एक पूरी साजिश है. विकास नगर के माई बाबा मंदिर के पास गश्त कर रही पुलिस को जानकारी मिली कि एक गैंग महिलाओं को ठग रहा है. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को दबोच लिया.

भाजपा और आरएसएस की पृष्ठभूमि से होगा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, कई नामों पर मंथन जारी

नई दिल्ली। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए नामों पर मंथन शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा का नया उम्मीदवार पार्टी के कोर काडर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि का हो सकता है। पार्टी के अंदर इस बात पर चर्चा है कि अति महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति केवल मूल विचारधारा से जुड़े लोगों की ही की जाए। दूसरे दलों से आए कई नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुके हैं। ऐसे में अब पार्टी महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते समय पार्टी को कोर विचारधारा से जुड़े लोगों के नामों पर ही विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद उनकी सहमति से इस पर अंतिम नाम पर मुहर लग सकती है। भाजपा ने हाल में चुनाव जीतने वाले राज्यों में जिस पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगाई है, उसे देखते हुए भी कहा जा सकता है कि पार्टी अब अहम जिम्मेदारियों के लिए केवल मूल विचारधारा से जुड़े नेताओं को ही प्राथमिकता देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने छात्र जीवन से एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। वे पार्षद होने के साथ-साथ संघ के कार्यों से भी जुड़ी रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी छात्र जीवन से

एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। महत्त्वपूर्ण विधेयकों को राज्यसभा से पारित कराने में उसकी भूमिका अहम होती है। ऐसे में इस पद पर पार्टी के मूल विचारधारा से जुड़े वरिष्ठ और अनुभवी नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। पार्टी में इस समय कई ऐसे नेता हैं जो इस समीकरण पर फिट बैठ सकते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन राज्यों से भी नया उपराष्ट्रपति लाए जाने पर विचार किया जा सकता है। दक्षिण के राज्यों से यह मांग उठने लगी है कि अब नया उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से बनाया जाए। इसी तरह सहयोगी दलों की मांग भी हो सकती है कि सत्ता संतुलन बनाए रखने में उनके नेताओं के नामों पर भी विचार किया जाए। हरिवंश पहले ही जदयू के कोटे से उपसभापति बनकर राज्यसभा का कामकाज देख रहे हैं। माना जा रहा है कि टीडीपी अपना महत्व बढ़ाने के लिए एनडीए के अंदर इस पद पर अपना दावा ठोंक सकती है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रकरण में पार्टी को चालू संसद सत्र में ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। जगदीप धनखड़ भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस और जनता दल में रह चुके थे। इसके पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने भी आपत्तिजनक बयानबाजी कर केंद्र सरकार को असहज करने का काम किया था।

वे भी कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, समाजवादी पार्टी और भारतीय क्रांति दल में रह चुके थे। जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी भी कई बार अपनी बयानबाजी से सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं।

पाकिस्तान को लंच- ट्रंप की पैंतरेबाजी

अमेरिका ने पहलगाम हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ को आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। इसका ज़मीनी मतलब यह है कि टीआरएफ को वित्तीय मदद देना अमेरिकी कानून के नीचे अपराध होगा। इस संगठन से जुड़े लोगों की अमेरिका में सम्पत्ति ज़ब्त होगी और अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकेंगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की कोशिश है। उनके विदेश विभाग का कहना है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा की 'प्राक्सी' अर्थात प्रतिनिधि है। मार्क रूबियो का यह भी कहना था कि उनका आतंकवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' है। हमारे विदेश मंत्री एस.जयशंकर के अनुसार यह सही समय पर लिया गया फ़ैसला है और यह 'आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की मज़बूत पुष्टि है'। हमारे अख़बारों की बड़ी सुर्खियाँ भी बता रही हैं कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त संदेश दिया गया है। पर क्षमा करें, मैं असहमत हूं। पहलगाम पर हमले के बाद टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर इसकी ज़िम्मेवारी कुबूल की थी। इसलिए यह कदम उठाना सही है पर ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान बाज़ नहीं आएगा। जिनके बारे कहा गया है कि वह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं होगा, अमेरिका में खाते होने का सवाल ही नहीं। खुद पीछे रह कर लश्कर-ए-तैयबा ने टीआरएफ को खड़ा किया है। इसके मुरीदके और भावलपुर जैसे मुख्यालय नहीं हैं जिन्हें आपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ध्वस्त किया था। पाबंदी के कुछ दिन शांत रहने के बाद यही लोग फिर सक्रिय हो जाएंगे। केवल बिल्ला बदलने की ज़रूरत है। इन लोगों के लिए भारत में ख़ून बहाना महत्व रखता है बिल्ला नहीं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जैश या लश्कर अपने नाम से हमले करें इसलिए टीआरएफ को आगे कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों ने कई नाम बदले हैं। अगली बार फिर कोई और नाम सामने आ जाएगा। मार्क रूबियो की घोषणा तीन महीने के बाद आई है। तीन महीने आप क्या देखते रहे जनाब? तीन महीने आपकी आतंकवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' क्यों सोई रही? इस दौरान पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भारी ऋण दिया गया। यह अमेरिका की सहमति के बिना नहीं हो सकता था। भारत शिकायत करता रहा कि आप आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हो पर आपत्ति की ज़रा परवाह नहीं की गई। सबसे शर्मनाक था डोनाल्ड ट्रम्प का पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित करना। बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस से निमंत्रण को तरसते है पर यहां पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने बैठ कर दो घंटे लंच किया। उस समय ईरान संकट चरम पर था पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति के लिए समय निकाला जिसे भारत आतंकवाद का खलनायक कहता है। मुनीर शायद पहला सेनाध्यक्ष है जिसे यह सम्मान मिला है। उसके बाद बहुत लापरवाह ढंग से हमारे प्रधानमंत्री को ट्रम्प ने कनाडा से वापिसी में व्हाइट हाउस में लंच पर रुकने का निमंत्रण दे दिया। यह तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने रुकने से इंकार कर दिया पर अमेरिका का रवैया बताता है कि उन्हें हमारी तकलीफों की चिन्ता नहीं। बार-बार युद्ध विराम का श्रेय लेकर ट्रम्प नरेन्द्र मोदी के लिए राजनीतिक समस्या खड़ी कर रहे हैं। अब कह दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच भिड़ंत के दौरान पांच विमान गिराए गए। यह तो नहीं बताया गया कि किसके विमान गिरे, पर भारत सरकार को तो अपने लोगों के आगे जवाबदेह बना दिया। सीडीएस जनरल चौहान यह तो स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध में नुकसान होता है पर मामला अस्पष्ट रखा गया। अब इस पर भी ट्रम्प दबाव बना रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि टीआरएफ पर पाबंदी बेमानी है, भारत सरकार को बजाने के लिए झुनझुना दे दिया गया है कि लोगों को बता सके कि बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हुई है। यह आई वॉश ही है। मुनीर के बाद पाकिस्तान के वायुसेना अध्यक्ष ज़हीर अहमद सिद्धू को वहां बुलाया गया। एक दशक के बाद पाकिस्तान के किसी वायुसेना अध्यक्ष की यह अमेरिका यात्रा थी। साफ़ है कि अमेरिका की सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मज़बूत करने में लगी है। इसका कारण उन्हें चीन से अलग करना है या ईरान से संघर्ष में उनका इस्तेमाल करना हो सकता है, पर यह सच्चाई है कि हमारी संवेदनाओं की उन्हें चिन्ता नहीं। हमें चुप करवाने के लिए टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका अब तक पाकिस्तान के 13 आतंकी संगठनों पर बैन लगा चुका है। यह कितने प्रभावी रहे यह पहलगाम पर हमले से पता चलता है। हाफ़िज़ सईद, मसूद अज़हर, दाऊद इब्राहीम सब पर बैन लग चुका है पर उनकी गतिविधियां बदस्तूर चालू हैं। अमेरिका तब सक्रिय होता है जब उसका अपना हित जुड़ा हो जैसे पाकिस्तान में घुस कर ओसामा बिन लादेन को मारा गया। हमारे किसी ऐसे मामले में न पहले सक्रियता दिखाई गई, न आगे दिखाई जाएगी। ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल पहले अवतार से बहुत अलग है। पहले पाकिस्तान ने और फिर इज़राइल ने ट्रम्प का नाम नोबेल सम्मान के लिए पेश कर अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल जीत लिया। भारत से वह ख़फ़ा है क्योंकि दो दर्जन बार दावा करने पर कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था, भारत उन्हें श्रेय नहीं दे रहा। अमेरिका के प्रमुख साथी देश, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया भी नाराज़ चल रहे हैं। ट्रम्प उनके नेताओं के साथ इंडो-पैसेफिक को लेकर वार्ता करना चाहते थे पर रोज़ की धमकियों और टैरिफ़ युद्ध से परेशान उन देशों के नेताओं ने मिलने से इंकार कर दिया। हमें भी धमकी दी जा रही है कि अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो भारी टैरिफ़ लगाया जाएगा। ट्रम्प चाहते है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध बंद कर दें। यह सही सोच है पर पुतिन बात नहीं मान रहे इसलिए दबाव डालने के लिए धमकी दी गई है कि अगर 50 दिन में युद्ध समाप्त नहीं किया तो उन देशों पर 100% टैरिफ़ लगाया जाएगा जो वहां से तेल लेते हैं। इन देशों में चीन और ब्राज़ील के साथ भारत भी शामिल है। एक अमेरिकी सेनेटर तो धमकी दे रहा है कि वह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। कहते हैं कि बड़े मियां सो बड़े मियां छोटे मियां सुभानअल्लाह। अमेरिका तो अपनी धौंस लगा रहा है पर अब नाटो के सचिव ने भी घोषणा कर दी है कि अगर भारत, चीन, ब्राज़ील रूस से तेल लेना बंद नहीं करते तो «मैं 100% दंडात्मक टैरिफ़ लगाऊंगा»। यह 'मैं' दिलचस्प है क्योंकि नाटो का अपना कोई देश नहीं और यूरोप के कई देश तीसरे देशों से रूस का तेल ख़रीदते है क्योंकि यह सस्ता है। लेकिन ट्रम्प को देखते हुए पश्चिम में बहुत लोग अहंकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन उन्हें सीधा कर चुका है। हमें भी स्पष्ट करना चाहिए कि एकतरफ़ा कदमों की बड़ी राजनीतिक क़ीमत हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच जिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बहुत ढंढोरा पीटा गया था वह अब कहीं नज़र नहीं आ रही। इसके विपरीत अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की खुशामद से ट्रम्प की ईगो प्रसन्न है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंक की सजा नहीं देने वाला। हां, क्योंकि चीन के खिलाफ़ क्वाड जैसे संगठन में हमारी ज़रूरत है इसीलिए हमें शांत करने के लिए टीआरएफ पर पाबंदी लगाने का झुनझुना पकड़ा दिया गया है ताकि सरकार को लोगों के बताने के लिए कुछ मिल जाए। पर यह भी स्पष्ट है कि अगर कल को चीन के साथ हमारा टकराव होता है तो अमेरिका से मदद की कोई आशा नहीं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर अमेरिका वास्तव में दबाव डालता तो वह देश कुछ सुधर जाता। आतंकवाद के प्रति अमेरिका की ढुलमुल नीति उन्हें और दुस्साहसी बनाएगी। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। डोनाल्ड ट्रम्प को खुश रखना एक ज़रूरत बन गई है। पर देश की इज़्ज़त से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को गोद में लेना है और हम पर पाबंदियां लगानी है तो यह आशा नहीं करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सहयोग करता रहेगा। हम किसी का मोहरा नहीं हैं। आशा है इस संसद अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी इन मामलों पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे और कड़ा जवाब देंगे। देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।

क्या सोच रही है हिंद-पाक की जनता सिंदूर के बाद!

आजकल व्हाट्सअप पर सब कुछ आ जाता है। पाकिस्तानी जनता से विभिन्न यूट्यूब चैनलों के एंकर पूछते हैं कि क्या भारत सिंदूर-2 करेगा तो वे राजनेताओं की तरह यह नहीं रटते कि ऐसा हुआ तो भरपूर ताक़त से जवाब दिया जाएगा, बल्कि नामचीन महिला पत्रकार आशूर काज़मी ने तो यहां तक कहा कि जब पाकिस्तानी दहशतगर्द (आतंकी) हिंदुस्तान के बेगुनाह बाशिंदों और फौजियों की जान लेंगे तो उनको पूरा अधिकार है बदला लेने का। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मोदी से पंगा ले कर पाकिस्तान ने भारी गलती की है। उन्होंने मोदी की इस बात की हिमायत भी की कि «गोली और बोली» साथ-साथ चलना असंभव है। एक अन्य युवक ने यहां तक कह दिया कि उन्हें मोदी जैसा शासक चाहिए न कि शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जैसे ढीले लोग! लाहौर से कराची, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के लोगों में सिंदूर-1 का दबदबा बैठा हुआ है और खौफ़ज़दा है कि कब सिंदूर-2 से पुनः पाकिस्तान को ठोका जाए। दिल्ली में आयोजित एक भारत-पाक संगोष्ठी में, जिसे «इंडो-पाक पीस प्लेटफार्म» के सर्वे सर्वा ओ.पी. शाह ने संयोजित किया था, इस बात का आभास हुआ कि आज पूरा पाकिस्तान किसी भी समय सिंदूर-2 होने के भय से ग्रसित बैठा है। यह मात्र 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के कारण नहीं, जहां 26 लोगों की मौत हुई थी, बल्कि, पाकिस्तान की उस मानसिकता के कारण है, जो एक लंबे समय से कभी छत्तीसिंह पुरा, कभी उड़ी, कभी पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों, आईएसआई व सेना द्वारा कत्ल किए बेगुनाह भारतीय नागरिक व सैनिक मारे जाते रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान इस डर से कांप रहा है, कि कब भारत उन से सिंदूर के खून का बदला चुका ले। इस संदर्भ में एक ओर जहां पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक, अशरफ जहांगीर काज़ी ने जहां भारत से संयम से सोचने की बात की, बल्कि हाथ जोड़े, वहीं उसके पूर्व मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भारत से युद्ध की धमकी दी, यदि पानी रोका गया। क्या पाकिस्तान धमकियां देने से उस समय बाज़ आएगा, जब उसकी ईंट से ईंट बज जाएगी! वास्तव में भारत-पाकिस्तान उसी प्रकार से सगे भाईयों की तरह हैं, जो 1947 के विभाजन के बाद बिछड़ गए। ये दोनों एक ही मां के बेटे हैं, जैसा कि भारत रत्न, मौलाना आज़ाद ने पंजाब के विभाजन के समय कहा था कि पानी को तलवार से काटा नहीं जा सकता। वे पाकिस्तान की स्थापना के सख़्त विरोधी थे और मुसलमानों से कहते थे कि उनकी धरोहर भारत में ही है और जब जिन्ना ने मुस्लिमों को बहकाया, भटकाया और भड़काया तो बहुत से पाकिस्तान चले गए। आज़ाद ने यह देखा तो बड़े दुखी हुए और एक दिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्हें रोकने का आह्वान किया कि उनकी धरोहर, संस्कृति, संस्कार, मस्जिदें, मदरसे उन्हें पुकार रहे हैं। विभाजन को लेकर आज़ाद के मन मस्तिष्क पर बड़ी गहरी चोट थी, ऐसे मुस्लिमों को उन्होंने ललकारा और लताड़ा कि जब आज़ाद ने दौड़ना चाहा तो उनके पांव तोड़ दिए, जब उन्होंने लिखना चाहा तो हाथ कलम कर दिए और जब उन्होंने बोलना चाहा, तो उनकी ज़ुबान पकड़ ली। उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पर आरोप लगाया था कि भारत के विभाजन के वे ज़िम्मेदार थे, क्योंकि गांधी ने आज़ाद को वचन दिया था कि अगर विभाजन हुआ तो उनकी लाश पर होगा, मगर नेहरू द्वारा बहकाए जाने पर गांधीजी भटक गए और विभाजन हो गया, मगर कांग्रेस की इस परिवारवादी मानसिकता ने हर स्थान पर नेहरू-गांधी को थोप और छाप दिया, जबकि आज़ाद, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को पूर्ण रूप से लुप्त कर दिया। इस वार्ता में कई पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तान को कोसा कि एक बड़े भाई की तरह उस से क्रॉस बॉर्डर लाभ उठाने चाहिए थे। नामचीन शायर, फैज़ अहमद फैज़ की बेटी, हलीमा ने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों की बेवकूफी के कारण हिंद-पाक मुशायरे, साहित्यिक व पत्रकारिता, नाट्य कला, खेल-कूद आदि गतिविधियों पर भी भारत ने रोक लगा दी है।

मुज़फ्फराबाद बस, लाहौर बस, समझौता एक्सप्रेस आदि भी ठप्प है। एक अन्य प्रसिद्ध लेखिका, बीना सरवर ने कहा कि अब भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने चाहिएं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म के बंद होने से या तो कई पाकिस्तानी जानें गंवा रहे हैं, या हज़ारों गुणा महंगे इलाज के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि जा रहे हैं और इन्सानियत का तकाज़ा यह है कि उसे बहाल करना चाहिए, मगर बीना को यह भी समझना चाहिए कि इन्सानियत का तकाज़ा यह भी है कि बेगुनाह हिन्दुस्तानियों की जान भी बराबर की कीमती है।

आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस किस-किस की पैरवी करेगी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरुआती चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वाड्रा को जानबूझ कर परेशान करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि राहुल के इस आरोप के चंद दिनों बाद ही ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भूपेश बघेल के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह घोटाला 2019-2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा है। सवाल यह है कि राहुल, सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार किस-किस कांग्रेस के नेता के भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को दुर्भावना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे शुरुआती चार्जशीट दायर की। इस मामले में ईडी की तरफ से 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से इस सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। यह आरोपपत्र है, उसी षड्यंत्र का ही एक और हिस्सा है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट शिखोपुर लैंड डील मामले में पेश की गई है। ईडी के मुताबिक वाड्रा ने यहां 3.53 एकड़ महज 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसे कुछ ही समय बाद वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था। अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 है। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी को वाड्रा के मामले में साजिश नजर आती है। लेकिन दूसरे घोटालों के मामलों में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में की चुप्पी साबित करती है कि कांग्रेस अपने अतीत को दोहरा रही है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन जिन गिने-चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती रहती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलार-चिक्कबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमुल) की 2023 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में कर्नाटक कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नानजेगौड़ा, कोमुल के अध्यक्ष भी हैं। ईडी के अनुसार कोमुल द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था, लेकिन पैसे और राजनीतिक सिफारिशों के बदले में इसमें हेरफेर किया गया था।

सम्पादकीय...

शहीदी शताब्दी पर सियासत क्यों?

गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिन्दू धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। गुरु जी की शहादत को नवम्बर माह में 350 साल होने जा रहे हैं मगर अफसोस कि जिन लोगों को गुरु जी की शहादत का प्रचार करना चाहिए था वह अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाए और आज उन लोगों के द्वारा शहीदी शताब्दी को सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इतना ही नहीं इसके लिए श्री अकाल तख्त साहिब और वहां के जत्थेदार का भी खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सिख कौम के लिए सही नहीं है। इतिहास में जब भी कोई शताब्दी आई तो उसे उसी स्थान पर मनाया गया जहां से उसका इतिहास जुड़ा हो। भाव 1999 में खालसा पंथ के 300 साल होने पर श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर समागम किए गए और समूचे सिख पंथ ने वहां पहुंचकर शताब्दी समारोह में भाग लिया। इसी प्रकार गुरु गोबिन्द सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व तख्त पटना साहिब की धरती पर मनाया गया। अब गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व नवम्बर में आ रहा है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का फरमान दिल्ली के लाल किला से सुनाया गया और चांदनी चौक में गुरु जी को शहीद किया गया। गुरु जी के धड़ का संस्कार भी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में हुआ इस हिसाब से गुरु जी की शहीदी शताब्दी के मुख्य समागम दिल्ली में होने चाहिएं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के द्वारा अपनी जिम्मेवारी का बाखूबी निर्वाह करते हुए शहीदी शताब्दी मनाने हेतु देश भर से धार्मिक जत्थेबंदियों की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की ओर से गुरचरन सिंह ग्रेवाल ने भाग लेकर मिलकर शताब्दी मनाने पर सहमति भी दी थी मगर ना जाने अब ऐसा क्या हो गया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अलग तौर पर पंजाब में शहीदी शताब्दी मनाने की बात कर रही है। इतना ही पंजाब सरकार के द्वारा जब शहीदी शताब्दी को पंजाब में सरकारी स्तर पर मनाने की बात कही तो उसके अगले ही दिन शिरोमणि कमेटी के प्रभावहीन कार्यरत जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री को गुरसिखी का पाठ पढ़ाते हुए अमृतपान करने की सलाह दे डाली। एक ओर तो इस कार्य के लिए जत्थेदार अकाल तख्त बधाई के पात्र है जिन्होंने हिम्मत दिखाकर मुख्यमंत्री को सिक्खी स्वरुप में आने की बात कही मगर उनके इस बयान के पीछे पूरी तरह से राजनीति की बास आ रही है। जत्थेदार अकाल तख्त को पंजाब के मुख्यमंत्री का सिक्खी स्वरूप सरकार के शहीदी शताब्दी मनाने के ऐलान के बाद ही क्यों दिखाई दिया जो कि जत्थेदार की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। अच्छा होगा जत्थेदार अकाल तख्त शिरोमणि कमेटी प्रधान को एकजुटता का पाठ पढ़ाएं और अलग से राग अलापने की जगह दिल्ली में हो रहे समागमों के लिए सहयोग देकर शताब्दी मनाने के लिए कहें। सिख कौम के पहले से ही अनेक मसले ऐसे हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है ऐसे में हजूर साहिब नांदेड़ की संगत के द्वारा एक नया विवाद कौम में खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिख लड़की की गैर सिख लड़के से शादी होने पर उस परिवार से हर तरह नाता तोड़ लिया जाएगा। इस फैसले को उन्होंने तख्त हजूर साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह जी के पास अन्तिम निर्णय के लिए भेजा है। हलांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है मगर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आज भी अनेक ऐसे सिख परिवार होंगे जिनमें गैर सिख परिवारों के साथ खून का रिश्ता होगा क्योंकि पहले के समय में हर गैर सिख परिवार घर के बड़े बेटे को सिख बनाया करता था। इतना ही नहीं ज्यादातर गैर सिख गुरुघर में पूरी तरह से आस्था रखते है और अपने हर कार्य को गुरु मर्यादा अनुसार ही करते है, इस फैसले के बाद वह लोग क्या करेंगे। सिख बुद्धिजीवी जतिन्दर सिंह साहनी का मानना है कि सिख लड़की के मामले में ही फैसला क्यों, अगर लेना ही था तो सिख लड़के पर भी लेना चाहिए था जो सिख लड़के गैर सिख लड़कियों से शादी करते उनका क्या होगा। सिख धर्म को गुरु साहिब ने मानस की जात सबै एक पहचानबे की बात कही थी। इतना ही नहीं सिखी तो गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अमृतपान करवाकर सिखों को दी उससे पहले तो सभी गैर सिख ही थे। इसलिए बेहतर होता अगर यह लोग सिख युवकों के केश कत्ल करने पर चिन्ता करते, सिखों के ईसाईकरण पर चिन्ता करते मगर इन्होंने सिख लड़कियों की शादी पर बयान देकर केवल नए विवाद को जन्म दिया है। आमतौर पर देखने में आता है कि सिखों के जितने भी स्कूल चल रहे है उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है जिसके चलते स्वयं सिख अपने बच्चों को वहां पढ़ाना पसन्द नहीं करते। मगर पंजाब के पुरी में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर चलता एक स्कूल ऐसा भी है जहां एक छत के नीचे 8200 बच्चे आस पास के 120 से अधिक गांवों से आकर शिक्षा ले रहे हैं। करीब 200 किले में बने इस स्कूल में मैनेजमेंट के नाम पर मात्र 2 से 3 लोग हैं जिनमें पंजाब के पूर्व डी आई जी परमजीत सिंह है जिनके मार्गदर्शन और प्रिंसीपल सतबीर सिंह जिन्हें खासतौर पर दिल्ली से लाया गया है उनके द्वारा दिये जा रहे निर्देशों पर स्कूल स्टाफ कार्य करता आ रहा है। स्कूल की खासियत यह है कि यहां पर एक भी सिफारिशी टीचर या बच्चा भर्ती नहीं किया जाता जिसके परिणाम ही स्कूल इस मुकाम तक पहुंचा है। बीते दिनों मुझे स्कूल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसे देखकर गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के शुरुआती दौर की याद ताजा हो गई जब इन स्कूलों में देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े राजनेताओं की सिफारिश पर दाखिला मुश्किल से मिला करता था। टीचर्स के सिफारिशी भर्ती होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मगर समय के साथ साथ स्कूलों का प्रबन्ध ऐसे हाथों में चला गया जिन्होंने अपनी कुर्सियां बचाने की खातिर स्कूलों को उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्हें एजुकेशन या स्कूल चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। उन चेयरमैनों और सदस्यों के द्वारा अपने पहचान के सिफारिशी टीचर्स भर्ती किए जाने लगे। जरूरत से ज्यादा भर्तियां होने के चलते तनख्वाह समय से ना मिलने और विपक्षी दलों के इशारे पर टीचर्स और स्टाफ ने कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया। जिसके बाद से मानो स्कूलों का पूरी तरह बर्बादी का दौर शुरु हो गया। आज हालात ऐसे बन चुके है कि कोर्ट के द्वारा प्रबन्धकों को स्कूलों की जायदाद बेचकर स्टाफ का बकाया देने की बात कही जा रही है हालांकि मौजूदा प्रबन्धक साफ कर चुके है कि एक ईंच जमीन भी बेची नहीं जाएगी।

सेहत के लिए शक्कर के खिलाफ़ विश्वयुद्ध

वैश्विक स्तरपर जहां एक और दुनियाँ युद्ध के साए में घिरी हुई है, तो दूसरी ओर अब मानवीय स्वास्थ्य को लेकर विश्व में दीर्घकालिक मंथन शुरू हो गया है। क्योंकि वर्षों पुरानी कहावत हेल्थ इज़ वेल्थ अब हर देश के सरकारों को पूरी तरह समझ में आ गई है,इसलिए अब 106 से अधिक देशों ने कार्बोनेटेड ड्रिंक पर विशेष कर या उपकर लगाया जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत में तो तंबाकू शराब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल स्मोकिंग डिवाइसेस एनर्जी ड्रिंक्स पर अधिक टैक्स लगाए जाते है,परंतु यूएई में इस पर अब 100 परसेंट टैक्स होगा,यानें अब वहां एक जनवरी 2026 से जिस कोल्डड्रिंक या किसी भी पेय पदार्थ में शक्कर अधिक होगी तो उसपर उतना ही अधिक टैक्स लगाया जाएगा, यानें अब टैक्स रिटेल प्राइस पर नहीं बल्कि अधिकतम चीनी प्रयोग पर टैक्स लगाया जाएगा तो, भारत में अभी स्कूलों शासकीय कार्यालयों सार्वजनिक स्थानों सहित हर जगह यथा यानें शक्कर की मात्रा विभिन्न खाद्य पदार्थों में कितनी है उस जानकारी के बोर्ड हर स्थान पर लगाने होंगे, क्योंकि अब पूरी दुनियाँ हेल्थ इस वेल्थ के सूत्र को स्वीकृत कर इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, मधुमेह मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कम करने, स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को वित्तीय प्रोत्साहन की वैश्वीकरण नीति लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं, इसीलिए सेहत के लिए शक्कर के खिलाफ विश्वयुद्ध, भारत से यूएई तक चीनी कम अभियान शुरू, यूएई में 1 जनवरी 2026 से कोल्डड्रिंक व पेय पदार्थों पर, चीनी आधारित टैक्स लगेगा। साथियों बात अगर हम चीनी के अधिकतम सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की करें तो,वैश्विक स्तरपर, चीनी के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, यकृत रोग और दांतों की सड़न शामिल हैं। इसलिए, चीनी के सेवन को कम करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक स्तरपर कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण है।चीनी, और विशेष रूप से मीठे पेय पदार्थों की खपत को कम करने के प्रयास में, दुनियाँ भर की सरकारों ने मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाने सहित कई रणनीतियां लागू की हैं।मेक्सिको ने 10 पेर्सेंट «चीनी कर» लागू किया है , जिसके परिणामस्वरूप चीनी- मीठे पेय पदार्थों की खपत में 12पेर्सेंट की कमी आई है। फ्रांस और चिली ने भी इसी तरह के कर लागू किए हैं, जबकि इंडोनेशिया, भारत और फिलीपींस जैसे अन्य देश चीनी पर कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। कैंसर रिसर्च यूके और यूके हेल्थ फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार , ब्रिटेन में चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाने से अगले 10 वर्षों में 37 लाख लोगों को मोटापे से बचाया जा सकता है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से ज्यादा ब्रिटिश जनता ने इस कर का समर्थन किया है। साथियों बात अगर हम संयुक्त अरब अमीरात में 1 जनवरी 2026 से मीठे पेय पदार्थों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की करें तो, यूएई मीठे पेय पदार्थों पर एक नया चीनी-सामग्री-आधारित उत्पाद शुल्क लागू करेगा, वित्त मंत्रालय और संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 को घोषणा की।यह कदम स्वस्थ उपभोग की आदतों को बढ़ावा देने तथा जनसंख्या में चीनी के सेवन को कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।संशोधित मॉडल के तहत, कर अब एक समान 50 प्रतिशत की दर से नहीं लगाया जाएगा।इसके बजाय, इसकी गणना प्रति 100 मिलीलीटर चीनी की मात्रा के आधार पर की जाएगी-अर्थात, उच्च चीनी स्तर वाले उत्पादों पर अधिक कर लगाया जाएगा, जबकि कम चीनी वाले लोगों को कम दर का भुगतान करना पड़ सकता है। यह पहल बेहतर आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने और मधुमेह व मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कम करने की यूएई की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है। स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर, अधिकारी उपभोक्ताओं और निर्माताओं, दोनों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक विकल्पों की ओर प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं।मंत्रालय ने एक बयान में कहा,«संशोधित ढांचा जन स्वास्थ्य और सतत कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। हम दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति का लाभ उठा रहे हैं साथियों बात अगर हम भारत में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स की करें तो,इसपर कई देशों में उच्च कर लगाया जाता है, जिसे अक्सर «चीनी कर» या «सॉफ्ट ड्रिंक टैक्स» कहा जाता है। भारत में भी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 28 पेर्सेंट जीएसटी और 12 पेर्सेंट क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, जिससे कुल कर 40 पेर्सेंट हो जाता है।उच्च कर का कारण– कार्बोनेटेड ड्रिंक, विशेष रूप से जिनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए, कई सरकारें इनपर उच्च कर लगाकर लोगों को इनके सेवन से हतोत्साहित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कोशिश करती हैं मीडिया के अनुसार, 106 से अधिक देशों में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर विशेषकर या उपकर लगाए जाते हैं।दरअसल, सरकार को इन ड्रिंक्स पर अभी तक लागू 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को कम किए जाने का अनुरोध मिला है,महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय वित्तमंत्री से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर लागू जीएसटी को तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया है,हालांकि, इस पर फैसला आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। साथियों बात अगर हम अधिक शक्कर सेवन से होने वाली स्वास्थ्य हानि की करें तो,इंसान की जीभ में पांच तरह के टेस्ट बड्स होते हैं। इनसे ही हमें मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और तीखे का अहसास होता है। इनमें सबसे शक्तिशाली है मीठे का स्वाद। इतना शक्तिशाली कि दुनिया की सबसे बेस्वाद और कड़वी चीजें भी शक्कर में लिपटी हों तो स्वादिष्ट लगने लगती हैं।दुनिया में अनगिनत लोग इसी मीठे के नशे में डूबे हुए हैं। इन लोगों को चीनी के स्वाद से मुहब्बत है। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि यह चीनी ही उनकी असली दुश्मन है। चीनी दुनिया का सबसे खतरनाक और एडिक्टिव ड्रग है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक चीनी इंसान के लिए किसी बंदूक से ज्यादा घातक है। ज्यादा चीनी खाने से हर तरह की बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इससे मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर्स जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये हेल्थ कंडीशन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकती हैं। साल 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी थी कि लोगों को अपना डाइट प्लान इस तरह बनाना चाहिए कि एक दिन के टोटल कैलोरी इंटेक का 5 परसेंट से ज्यादा ऐडेड शुगर से न आए। यानी अगर आप दिनभर में 2,000 कैलोरीज ले रहे हैं तो अधिकतम 100 कैलोरी ही ऐडेड शुगर से आए। यह लगभग 6 चम्मच चीनी खाने के बराबर होगा।अधिक चीनी खाने से कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन, कुछ असर नजर आ सकते हैं। (1) थकान महसूस होती है। (2) मूड खराब हो जाता है। (3) पेट में आती सूजन- (4) ज्यादा भूख लगती है।ज्यादा चीनी खाने से लंबे समय में होने वाले नुकसान बेहद खतरनाक हैं।(5)दांत सड़ सकते हैं (6) मुंहासे हो सकते हैं। (7) बढ़ सकता है वजन और मोटापा (8) टाइप-2 डायबिटीज का खतरा (9) ब्लड प्रेशर बढ़ता है।(10) कार्डियोवस्कुलर डिजीज का खतरा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सेहत के लिए शक्कर केखिलाफ़ विश्वयुद्ध-भारत से यूएई तक चीनी कम अभियान-यूएई में 1जनवरी 2026 से चीनी आधारित टैक्स सिस्टम लागू सेहत के लिए शक्कर एक धीमा जहर है,इसके खिलाफ़ भारत के साथ यूएई ने भी कमर कसी- दीर्घकालीन रणनीति पर काम शुरूमधुमेह मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कम करने, स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को वित्तीय प्रोत्साहन की वैश्विक रणनीति सराहनीय है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैराडाइज़ एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/0882)

जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की करी बैठक

उद्यमियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारी को किया गया निर्देशित

बरेली।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में पाया कि निवेश मित्र पोर्टल पर यू.पी.सी.डा. के 10 प्रकरण समय सीमा से बाहर लंबित हैं, जिस पर क्षेत्रीय प्रबंधक यू.पी.सी.डा. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि छः प्रकरण मुख्यालय स्तर पर लंबित हैं शेष पर शीघ्र पर निस्तारण कराया जा रहा है। कुछ टेक्निकल समस्या प्रदेश स्तर पर होने के कारण प्रकरण लंबित हुए हैं। बैठक में ग्राम पीपलसना चौधरी स्थित औद्योगिक क्षेत्र भोजीपुरा में पानी निकास की समस्या रखी गयी, जिसमें बताया गया कि सम्बंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर पानी की निकासी नदी तक पहुंचाने हेतु स्टीमेट बना लिया गया है। जिस पर उद्यमियों ने बताया कि भोजीपुरा में कार्य हेतु बजट आया नहीं है अन्य स्थानों का भी सर्वे कर आगणन भेज दिया गया है, एक-एक करके समस्याओं को निस्तारण किया जाए। बैठक में उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल रोड पर बरेली से बहेड़ी तक स्ट्रीट लाइट लगायी गयी हैं परन्तु रिछा रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हैं, जिस पर अवगत कराया गया कि स्टीमेट बनाकर भेजा जा चुका है, निर्देश दिए गए कि रिछा का स्टीमेट अलग से भेजा जाए और धनराशि आने पर कार्य कराया जाए। बैठक में उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि रिछा-जहानाबाद रोड पर विगत वर्ष रोड साइड के किनारे एक ओर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा चुका है दूसरी ओर भी इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाए, जिस पर अधिशासी अधिकारी रिछा द्वारा अवगत कराया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर आगणन तैयार कर लिया गया है अगली बोर्ड बैठक में स्वीकृति लेते हुए कार्य कराया जाएगा। बैठक में उद्यमियों द्वारा रिछा-जहानाबाद रोड पर अटल मिशन योजना के अंतर्गत हाई मास्क लाइट व स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु कहा गया, जिस पर अवगत कराया गया कि उक्त योजनान्तर्गत सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में ही कार्य कराया जा सकता है।

भागवत प्रसाद मेमो0 इंटर कॉलेज बांदा में जल संरक्षण व वृक्षारोपण पर एक जीवन सुधा फाउंडेशन द्वारा संगोष्ठी का हुआ आयोजन

बांदा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित पंजीकृत संस्था जीवन सुधा शिक्षा, जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण फाउंडेशन, संक्षेप में जीवन सुधा फाउंडेशन ÷द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2025 को शहर के भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज बांदा में, जल संरक्षण व वृक्षारोपण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस अवसर पर संस्था के प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र सिंह जी ने बच्चों को अपने दैनिक कार्यों में पर्यावरण को संरक्षित करने के विभिन्न उपाय बताए 7 संस्था के संस्थापक एवं मुख्य मार्गदर्शक श्री श्रीराम सिंह लोध जी ने बताया कि जल जीवन के लिए पृथ्वी का अमूल्य वरदान है ,अतएव वर्तमान वर्षा के मौसम में ,जल को सहेजने के सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अभियान कैच द रेन ÷के तहत वर्षा जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ,खेतों की मेड बंदी, व खेतों की गहरी जुताई के द्वारा, भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करना अति आवश्यक है । उन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु ,बच्चों से अपने दैनिक उपयोग में जल का सदुपयोग व अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया । संस्था के सदस्य श्री राजेंद्र यादव जी ने पर्यावरण को संरक्षित करने के उपायों के साथ ही जीवन में सफलता के गुर बताए । कृषि विशेषज्ञ श्री हनुमान दास राजपूत जी ने वर्षा जल से खेतों को होने वाले लाभ व वर्ष भर खेती करने हेतु उसे सहेजने के कई उपायों का वर्णन किया । इस अवसर पर विद्यालय कैंपस में औषधि गुणों से युक्त हरसिंगार व मौलश्री नामक पौधों का रोपण, प्रधानाचार्य, शिक्षक स्टाफ व संस्था की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया । विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर सहयोग करने हेतु विद्यालय स्टाफ के सर्वश्री ललित कुमार, महेश कुमार ,लक्ष्मी देवी ,हरि शरण विश्वकर्मा ,अरविंद कुमार राजपूत, रावेंद्र सिंह व राजकुमार जी उपस्थित रहे ।

फर्जी अकाउंट से रिश्तेदारों को भेजीं आपत्तिजनक फोटो, आरोपी मांग रहा रंगदारी, सऊदी में रह रही महिला का बनाया इंस्टा पर फर्जी अकाउंट

बरेली।

सोशल मीडिया पर एक महिला की छवि बिगाड़ने और उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता मूल रूप से बरेली की रहने वाली है और वर्तमान में अपने पति के साथ सऊदी अरब में रहती है। आरोप है कि शाहजहांपुर निवासी युवक ने फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने की साजिश रची और पीड़िता के पति से तीन लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी। बारादरी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने बताया कि उनकी बहन का निकाह दो वर्ष पहले हुआ था और वह सऊदी में अपने पति के साथ रह रही है। इसी दौरान शाहजहांपुर का रहने वाला अजहर खान उर्फ अज्जू अपने साथी इमरान के साथ मिलकर उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है। दोनों आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल और मैसेज भेजते रहे हैं। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता की तस्वीरों को एआई की मदद से एडिट कर अश्लील बना दिया और उसे इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट से रिश्तेदारों को भेज दिया। इसके अलावा आरोपियों ने पीड़िता के पति को भी इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर तीन लाख रुपये की डिमांड की। रंगदारी न देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। जब महिला को यह जानकारी मिली तो उसने परिजनों को बताया, जिसके बाद उसके भाई ने बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला साइबर क्राइम, आईटी एक्ट और रंगदारी की धाराओं में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

राजकीय महिला महाविद्यालय में शास्ता मण्डल की आवश्यक बैठक का हुआ आयोजन

बांदा।

राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर दीपाली गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्य शास्ता डाक्टर सबीहा रहमानी के द्वारा शास्ता मण्डल की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया । इस समय महाविद्यालय में बीए, बीएससी, एम ए की द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं समेस्टर की कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है । शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु निम्न बिन्दु निर्धारित किए गए -अनुशासन एवं एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए यूनीफार्म कोड निर्धारित है सफेद सूट और मैरून दुपट्टा, जो छात्राएं हिजाब धारण करती हैं वे महाविद्यालय में सफेद सूट, मैरून दुपट्टा और सफेद या मैरून हिजाब पहनकर आ सकती हैं । मुस्लिम छात्राएं यदि बुरका/ नकाब पहनतीं हैं तो वह घर से महाविद्यालय तक पहन कर आयेंगी किन्तु महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाएं में अनुशासन और अकादमिक एकरूपता को बनाए रखने हेतु महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की गई यूनीफार्म व हिजाब को पहनेंगी । महाविद्यालय में बारम्बार यूनीफार्म की अनिवार्यता की सूचना के बावजूद यदि छात्राएं यूनीफॉर्म में नहीं आतीं तब उन्हें चेतावनी, अर्थदंड फिर भी न मानने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । अगस्त के प्रथम सप्ताह से कक्षाएं सम्भावित हैं 75 फीसदी उपस्थिति को ध्यान में रखकर छात्राएं अपनी कक्षाओं में नियमित रुप से उपस्थित रहेंगी ।

छात्राएं अवगत हों कि महाविद्यालय में सूचना पटल पर विभिन्न समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रतिदिन आवश्यकता के अनुरूप चस्पा की जाती हैं। अत महाविद्यालय उपस्थित होकर स्वयं सभी सूचनाओं का अवलोकन करें । यह आवश्यक नहीं है कि आपको किसी प्रकार की सूचना आनलाइन दी जाए । शासन द्वारा निर्देशित आकस्मिक सूचनाएं ही आवश्यकता पड़ने पर आनलाइन सूचित की जायेंगी इस बैठक में समस्त सदस्य शास्ता मण्डल एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक उपस्थित रहे । विगत वर्षों की भांति सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए गए ।

दोस्त ने ही बना डाला 16 लाख का कर्जदार, अब दे रहा जान से मारने की धमकी

बरेली।

किला क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को अपने ही दोस्त पर भरोसा करना भारी पड़ गया। पीड़ित ने बताया कि असद खान ने पहले दोस्ती की आड़ में उसका विश्वास जीता, फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर 16 लाख से ज्यादा की रकम हड़प ली। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो वह धमकियां देने लगा। पीड़ित ने किला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुलाबनगर निवासी अकलीम रजा के मुताबिक असद खान उसका पुराना पहचान वाला था। पहले उसने दोस्ती का फायदा उठाकर अकलीम का क्रेडिट कार्ड ले लिया और पेट्रोल पंपों, दुकानों व अन्य जगहों से करीब तीन लाख रुपये की खरीदारी और नकद निकासी की। असद ने दिखावे के लिए यह रकम दोबारा अकलीम के खाते में ऑनलाइन भेज दी ताकि शक न हो। इसके बाद असद खान ने बाजाज फाइनेंस से अकलीम के नाम पर 4.29 लाख का लोन भी पास करा लिया। शुरुआती दो-तीन ईएमआई खुद भरी, लेकिन बाद में किश्त भरना बंद कर दिया। अब यह लोन अकलीम के नाम पर बकाया है और वसूली के लिए नोटिस आ चुके हैं। आरोपी ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर अकलीम से अलग-अलग किस्तों में 4.46 लाख भी ले लिए। फिर दुकान खरीदने के नाम पर करीब 7 लाख की मांग की, जिसमें से अकलीम ने दीपक पटेल और नसीम नामक दोस्तों से उधार लेकर 6.65 लाख आरोपी को नकद दिए। अब जब अकलीम ने पैसे वापस मांगे, तो असद ने उल्टे उसे ही फंसाने की कोशिश की और झूठी शिकायतें करने लगा। इतना ही नहीं, हाल ही में वह अपने कुछ साथियों के साथ मस्जिद पहुंचा और अकलीम को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के पास आरोपी की ऑडियो, चैटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मौजूद हैं।

मां की बीमारी बताकर मांगा क्रेडिट, और हड़प ली 16 लाख से ज्यादा की रकम

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी में राजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फ्रंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया -सक्षम भारत

अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के इतने व्यस्त कार्यक्रम क्यों हैं? क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है?

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही ग्लोबल लीडर नहीं कहा जाता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने और भारतीय कूटनीति को नये मुकाम पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने भारत की पारंपरिक कूटनीति को वैश्विक मंचों पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई है। उनके नेतृत्व में भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, बल्कि नीति-निर्माण, रणनीतिक संतुलन और बहुपक्षीय गठबंधनों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही विदेश नीति को नई गति दी है। अभी हाल ही में वह पांच देशों की यात्रा से लौट कर आये हैं और इस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत बनाना और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करना है। इसके अलावा, आगामी कुछ महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी महीनों की यात्रा योजना और कूटनीतिक कार्यक्रम भारत की विदेश नीति में एक गहन, सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। चीन, अमेरिका, जापान, रूस और इंग्लैंड देशों से जुड़ी आगामी बैठकें न केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत व्यस्तताओं का प्रमाण हैं, बल्कि यह भारत की रणनीतिक विदेश नीति का प्रतिबिंब भी हैं, जिसमें बहुध्रुवीयता, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा स्पष्ट झलकती है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित चीन यात्रा, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण दिनों के बीच इस मंच पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति द्विपक्षीय संवाद के लिए अवसर दे सकती है। यह भारत की उस विदेश नीति को रेखांकित करता है जो टकराव के बजाय संवाद और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से समाधान को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की संभावना इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अग्रसर है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए जारी अस्थायी वक्ताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया है। यदि यह कार्यक्रम यथावत रहता है, तो मोदी 26 सितंबर 2025 को महासभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इस सूची में नामों को संक्षिप्त देशों की सहमति से शामिल किया जाता है और अंतिम समय तक इसमें बदलाव संभव होता है, फिर भी इस सूची में प्रधानमंत्री का नाम शामिल होना उनकी संभावित अमेरिका यात्रा की ओर संकेत करता है। यदि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तो भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में भी यह यात्रा निर्णायक हो सकती है, विशेषकर जब दोनों देशों के बीच शुल्कों और कृषि उत्पादों जैसे मुद्दों पर ठोस समझौते की तलाश की जा रही है। इसके अलावा, जापान, भारत का एक प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति के साझा लक्ष्य रखते हैं। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा क्वॉड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जो एक उभरता हुआ भू-

रूसी प्लेन चीन सीमा के पास क्रैश, सभी 49 लोगो की मौत

नई दिल्ली । रूस का एक यात्री विमान चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। हादसे में विमान में सवार 49 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचावकर्मियों को टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला है।। रॉयटर्स के मुताबिक ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में उड़ रहा था। अमूर के गवर्नर वासिली ओरलोव ने टेलीग्राम पर बताया कि लापता विमान अंगारा एयरलाइंस का है। लोकल इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान खाबरोवस्क, ब्लागोवेशचेंस्क होते हुए टिंडा जा रहा था। यह चीन की सीमा के पास है। टिंडा पहुंचने से पहले यह रडार से गायब हो गया और उसका संपर्क टूट गया। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, विमान पहले टिंडा एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश में नाकामयाब रहा।

जब उसने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, तभी वह रडार से गायब हो गया। तास समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि यह विमान टिंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एक तय चेकपॉइंट पर भी संपर्क नहीं कर पाया। टिंडा शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6,600 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है।

बिहार चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला, तेजस्वी बोले- सभी दलों से करेंगे बात

नई दिल्ली ।

राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट्स में ऐसा संकेत क्या दिया कि विपक्षी दलों ने उन्हें घेर लिया. तेजस्वी यादव ने कहा था, चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हो सकती है. हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है. सब लोगों की क्या राय है. जब आप जब आपने बेईमानी से सब कुछ तैयार कर रखें है कि इसको इतना सीट देना है, उसको इतना सीट देना है तो चुनाव ही मत कराओ. तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा, जब सब कुछ तय हो ही गया है, बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है... वोटर लिस्ट से लाखों का नाम कट देना है. इसी वोटर ने कई सरकारें चुनी हैं. जब बेईमानी करना है तो हम लोग मिलकर बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं. हम महागठबंधन में सभी दलों से बात करेंगे. चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा... जब जनता ही वोट नहीं देगी तो क्या मतलब रहेगा. हम लोग गंभीर होकर चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं. ये विकल्प हमारे पास खुला है... ये लोग मिले हुए हैं. ये असली खेला अभी ये लोग 1 अगस्त के बाद करेंगे. चुनाव आयोग नया खेला खेलने जा रहे हैं. हम लोगों की नजर है. जनता-गरीब का अधिकार छीनना है तो चुनाव का क्या मतलब है, ऐसे ही एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को...

जेडीयू बोली- क्या कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश

तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा आरोप लगाया है. त्यागी ने कहा, 28 तारीख को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. क्या उन्हें कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है. कहीं ये कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है , धमकी तो नहीं है ?

जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा फैसला लेंगे- बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हम यह जंग जारी रखेंगे और जरूरत आई तो बड़े से बड़ा फैसला लेंगे. आने वाले वक्त में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है. हम आखिरी लिस्ट और कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे. अगर वोटर के बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे. बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने चुनाव बहिष्कार के सवाल पर कहा कि सभी विकल्प खुले है , हम मिल जुलकर फैसला लेंगे. ये चुनाव आयोग का और ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट है.

वो अंतिम विकल्प है- पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, अगर तेजस्वी ने ये बात कही है तो उन्हें स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट और संसद के साथ है. जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे... उस पर तेजस्वी ने कहा है कि वो अंतिम विकल्प है. उससे पहले हम सब लोग मिलकर दोनों सदनों से इस्तीफा देकर और सत्ता पक्ष को अकेले सदन चलाने दें.

तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा-मनोज झा

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, भारत के चुनाव आयोग का रवैया अगर बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन जैसा होगा तो राजनीतिक दलों और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा. वो एक भी विदेशी वोटर का नाम बता दें. अगर वो बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं.

प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- अभी पुरानी स्थिति बहाल रखें

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये फैसला सिर्फ सीतापुर जनपद के लिए आया है। कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के मर्जर के फैसले को सही ठहराया था। इस मामले को एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचियों की ओर से बुधवार को जेष्ठ अधिवक्ता डॉ एलपी मिश्र व अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलीलें दीं। राय सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ बहस की।

भारत-यूके के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर

लंदन । भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। इससे ब्रिटिश विस्की, कारों और कई वस्तुओं पर टैरिफ में कमी आएगी। इसके साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी होगी।

समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। समझौता महज आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और स्वस्थ क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं विकासवाद है। इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इस एफटीए से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को फायदा होने की उम्मीद है। इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में व्हिस्की, कारों और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा। इससे समग्र व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों की जगह नहीं, स्टार्मर से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी

कांग्रेस ने धनखड़ के लिए विदाई समारोह की मांग उठाई, सरकार ने साध रखी है चुप्पी

नई दिल्ली । जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, वहीं पार्टी ने उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित करने की मांग की है। एक ऐसा अनुरोध जिस पर केंद्र सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। यह मांग धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बढ़ती राजनीतिक चर्चा के बीच आई है, जिसे स्वास्थ्य कारणों से बताया जा रहा है।

हालांकि, विपक्षी नेता सरकार से स्पष्टता की मांग करते रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह मांग उठाई थी। हालांकि, सरकार चुप रही और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने भी इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बताया कि किसी अन्य विपक्षी नेता ने रमेश की इस मांग का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस तीन साल तक पद पर रहे धनखड़ के लिए सम्मानजनक विदाई की मांग कर रही है। विपक्षी दल धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस स्वीकार करने के बाद धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। वर्मा के आवास से कुछ महीने पहले नोटों की जली हुई गड्डियां बरामद हुई थीं। यह मांग ऐसे समय में उठाई गई है जब गुरुवार को राज्यसभा अपने छह सदस्यों को विदाई दे रही है। अंबुमणि रामदास, वाइको, पी विल्सन, एम षणमुगम, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और एन चंदशेखरन को विदाई दी जा रही है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 2006 ट्रेन धमाके के आरोपियों को मिली थी राहत

नई दिल्ली। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने फैसले में धमाके के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जेल से रिहाई को बरकरार रखा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एस कोटिश्वर सिंह ने सभी आरोपियों को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं, वे जमानत हासिल करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि सोमवार को, बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। उच्च न्यायालय का फैसला महाराष्ट्र एटीएस के लिए बड़ा झटका है। एजेंसी का दावा है कि आरोपी प्रतिबंधित छात्र संगठन सिमी के सदस्य थे और उन्होंने ही पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्यों के साथ मिलकर बम धमाके की साजिश रची थी।

अमरनाथ यात्राः जम्मू आधार शिविर से 3,500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

श्रीनगर। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बृहस्पतिवार को 3,500 श्रद्धालुओं का नया जत्था दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, 22वें जत्थे में 2,704 पुरुष, 675 महिलाएं, 12 बच्चे और 109 साधु-साध्वियां शामिल हैं। यह जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 140 वाहनों के दो काफिलों में पहलगाम और बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इनमें से 2,668 श्रद्धालु 95 वाहनों के काफिले में पहलगाम मार्ग के लिए जबकि 45 वाहनों के काफिले में 832 श्रद्धालु बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए।

कब्जामुक्त करायें जमीन, पीड़ितों को दिलायें हक - सीएम योगी

गोरखपुर ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाये। गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में योगी ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक महिला ने जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाये। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाये। एक अन्य महिला की जमीन संबंधी शिकायत पर उन्होंने कहा कि महिला को उनकी जमीन का हिस्सा दिलाया जाये। जमीन का मामला यदि किसी परिवार का है तो दोनों पक्षों के बीच संवाद कर उसका निस्तारण कराये। हर पीड़ित को हक दिलाया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी।

प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाये। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में गिरी यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस, सात की मौत, 22 घायल

सरकाघाट(मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में मसेरन के पास तरांगला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। हादसे में सात यात्रियों की मौत हो गई है। करीब 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में पांच महिलाएं व दो पुरुष शामिल हैं। दो घायल महिलाओं ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के दौरान दम तोड़ा। घायलों का सरकाघाट अस्पताल व नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल हुए कंडक्टर सहित छह लोगों का उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने हादसे की पुष्टि की है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी सरकाघाट व पुलिस थाना की टीम मौके के लिए रवाना हुई। घायलों को एंबुलेंस से सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में जुटे रहे। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान बस में करीब 29 लोग सवार थे।

चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की- राहुल

इंटेंसिव रिविजन के विरोध के बीच चुनाव आयोग पर कर्नाटक में भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राहुल ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि वोटर लिस्ट रिविजन के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जोड़े गए। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई। हमारे पास इसके 100त सबूत है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों-हजार नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है

'हजारों बोगस वोटर जोड़े, हमारे पास 100 फीसदी सबूत; बच जाएंगे, इस गलतफहमी में न रहें

और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमें अभी एक सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने यह बातें चुनाव आयोग के उस बयान के बाद कही है, जिसमें बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन प्रोसेस का बचाव किया गया था।

'चुनाव आयोग बोला- राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर सोचिए

कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, वरना बेबुनियाद आरोप न लगाएं, राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक

चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बयान में अपने आलोचकों से सवाल पूछा कि क्या मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति देनी चाहिए।

चुनाव आयोग ने पूछा, रिविजन प्रोसेस का मकसद सिर्फ अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है। क्या चुनाव आयोग के पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है?

आयोग ने कहा, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर चुनाव आयोग की कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के विरुद्ध जाकर, पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक वोटरों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके वोटरों, दो जगहों पर वोट देने वाले, फर्जी या विदेशी वोटरों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता साफ कर देना चाहिए?

चुनाव आयोग ने कहा, इन सवालों पर, कभी न कभी, हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को, राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर, गहराई से सोचना होगा। और शायद आप सभी के लिए यह सोचने का सबसे अच्छा समय अब आ गया है।